Removal of Chairman-cum-Managing Director, Oil India Ltd.

153. SHRI GURUDAS DAS GUPTA :
SHRI CHATURANAN MISHRA :

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chairman-cum-Managing Director of the Oil India Limited, Maj. Gen. S. C. N. Jatar was removed from the post;

(b) if so, when and where he was posted thereafter;

(c) whether it is also a fact that this was done by succumbing to the longstanding demand of the All Assam Students Union (AASU);

(d) if so, whether the public sector executives, particularly those working in the Oil Industry, have expressed their concern over this move of Government; and

(e) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT) : (a) and (b) Maj. Gen. S. C. N. Jatar, Chairman-cum-Managing Director, Oil India Limited has been appointed to a higher grade Post in Schedule "A" in Hydrocarbons India Limited.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.

Demand of Preferential Treatment by Assam Government

154. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Assam Government had demanded preferential treatment for the use of natural gas produced in the State and for imposing conditions on the grounds of Petroleum Exploration Licences to public sector companies in that State ;

(b) if so, what are the details thereof ; and

(c) what is Government's decision in respect thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT) : (a) Yes, Sir.

(b) The Assam Government has requested for imposition of two conditions in the Petroleum Exploration Licenses/Leases. These conditions are (i) priority right to State for use of gas within the State (ii) applicability of formula devised by State Government for pricing of gas.

(c) Government of India has not agreed with these demands.

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

155. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें होनी थी और उक्त अवधि में इसकी वास्तव में कितनी बैठकें हुई तथा वांछित संख्या में बैठकें न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) पिछले 18 वर्षों से राजभाषा अधिनियम तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं तथा क्या इसे 1987-88 के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजभाषा विभाग से प्राप्त पत्रों, आदेशों आदि की संख्या क्या है तथा उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है ;

और

(घ) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव, अध्यक्ष और सदस्य अपने समूचे काम का कितना प्रतिशत भाग राजभाषा हिन्दी में कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जानी चाहिए । तद्नुसार पिछले दो वर्षों में आठ बैठकें आयोजित की जानी थीं । प्रति वर्ष निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजन करने के यद्यपि सभी संभव प्रयास किए जाते हैं, फिर भी पिछले दो वर्षों में केवल चार बैठकें ही आयोजित की जा सकी ।

(ख) राजभाषा अधिनियम तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं । पत्राचार के लिए निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करने ; अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने ; कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करने ; प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध करने ; कार्यशालाओं का आयोजन करने ; हिन्दी दिवस/सप्ताह मनाने ; हिन्दी कार्य के लिए आवश्यक स्टाफ और यान्त्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि के लिए पहले ही कार्रवाई की गई है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा राजभाषा विभाग से प्राप्त पत्रों, आदेशों आदि की संख्या निम्न प्रकार है :—

1. औद्योगिक विकास विभाग ..	341
2. कंपनी कार्य विभाग . .	171
3. सरकारी उद्यम विभाग . .	253
4. रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग	

क्योंकि यह विभाग हाल ही में बना है, इसलिए इसके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई आंकड़े नहीं है ।

सभी पत्रों/आदेशों आदि को, जिन पर सूचना और कार्यान्वयन के लिए परिचालन की कार्रवाई करना आवश्यक था, निपटा लिया है और इनमें से कुछ पर कार्यान्वयन की कार्रवाई चल रही है।

(घ) जहां तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव का संबंध है, वे शतप्रतिशत सरकारी कार्य हिन्दी में कर रहे हैं । अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हिन्दी में किए गए कार्य की सही प्रतिशतता उपलब्ध नहीं है । तथापि हिन्दी में अधिकाधिक कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

Execution of Gas Turbines Power Projects on the HBJ Pipeline

156. **SHRI SANTOSH BAGODIA:**
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK :
SHRI MAHENDRA PRASAD :

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have since taken a decision on the selection of contractors to execute the three gas turbine combined cycle power projects on the H.B.J. gas pipeline in Raajsthan, Gujarat and U.P. ;

(b) if so, what are the deails thereof;

(c) by when the work will commence on these projects ; and

(d) what are the details regarding funds allocated for each project?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) to (d) The World Bank have appraised the proposals in respect of award of contracts for the three gas-turbine combined cycle power projects of the National Thermal Power Corporation. The Corporation have intimated that pre-award negotiations are in progress and that contracts are expected